नए केरल के निर्माण में पुरानी चुनौतियां

लेखक-एम. ए. ओमन (मानद फैलो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 फरवरी, 2019

"नवा (Nava) केरल मिशन को विकेंद्रीकृत योजनाओं और स्थानीय सरकार की भागीदारी की आवश्यकता है।"

केरल सरकार के लिए, नवा केरल (नया केरल) मिशन, जिसका उद्देश्य चार प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना है, 2018 की बाढ़ के बाद एक बड़ी चुनौती बन कर रह गया है। राज्य सरकार के सहयोग से 76 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा तैयार की गई पोस्ट-डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट (PDNA) रिपोर्ट का अनुमान है कि 31,000 करोड़ रूपए, जो कि 2018-19 में जीएसडीपी (GSDP) का 4% था, राज्य के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। 17,316 घरों का पुनर्निर्माण, 46,000 घरों की मरम्मत करना, 1,613 स्कूलों का पुनर्निर्माण करना आदि अत्यंत कठिन कार्य हैं। इस चुनौती को एक अवसर में बदलना लोगों की इच्छाशक्ति और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पुनर्निर्माण मरम्मत से अलग होता है और विकास की अवधारणा और रणनीति में प्रतिमान बदलाव की मांग करता है। एक समग्र दृष्टिकोण प्रचलित तदर्थ दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर देगा। पीडीएनए रिपोर्ट इसके लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है।

शक्तियां और कमजोरियां

किसी भी उद्देश्यपूर्ण पुनर्निर्माण के लिए, हमें राज्य की शक्ति और क्षमताओं के साथ-साथ इसकी प्रमुख विफलताओं की पहचान करने की आवश्यकता है। केरल में एक आकर्षक मानव विकास इतिहास और एक समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। 1957 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता केरल में आयी, तब राज्य ने जमींदारवाद को समाप्त कर दिया, साक्षरता दर को 90% से अधिक ले जाने में सफल रहा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, लोगों के नियोजन को सुनिश्चित किया और विदेशी प्रेषण की आमद को बढ़ाया। हालांकि, सामाजिक असमानताएं: जैसे समाज के सबसे कमजोर वर्गों का हाशिए पर जाना, अपराध दर में वृद्धि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार का बढ़ना, आत्महत्या दर बढ़ना और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने जैसी समस्याओं को नीति निर्माताओं द्वारा अनदेखा किया गया है।

एंटोनियो ग्राम्स्की ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि राजनीति का मतलब एक सामान्य लक्ष्य की खोज में सचेत कार्रवाई (प्रैक्टिस) है। जबकि प्रतिकूल राजनीति लोकतांत्रिक प्रथा का हिस्सा है, केरल का जो ध्रुवीकरण दृष्टिकोण है, वह पुनर्निर्माण के संदर्भ में आज भी अप्रभावी है। चर्चा के माध्यम से नए राजनीतिक मुहावरे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई भी समाज विश्वास और खुलेपन के कुछ अनुमान के बिना सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। राज्य को महत्वपूर्ण पारदर्शिता की गारंटी की आवश्यकता है। पारदर्शिता भ्रष्टाचार, वित्तीय गैर जिम्मेदारी और व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून की बढ़ती उपेक्षा पुनर्निर्माण का आधार नहीं हो सकती है।

आज केरल से कहा जाता है कि वह पुनर्जागरण की भावना को वापस लाए। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। यह मानवता के सार की खोज और पुन: खोज कर रहा है, जिसे हाल के दिनों में नजरंदाज किया जा रहा है। यूरोप में प्रबुद्धता की तरह जिसने धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ तर्क दिया, नारायण गुरु ने उन लोगों के लिए स्वतंत्रता का महत्व सामने लाया, जो जाति और वर्ग के आधार पर पीड़ित थे।

परियोजना के लिए स्थानीय सरकार की भागीदारी और विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता होती है। लगभग 22,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले केरल में शासन के तीसरे स्तर को इसकी बहुस्तरीय योजना प्रक्रिया और लोगों की भागीदारी के लिए जाना जाता है। इसलिए स्थानीय सरकार को वसूली और पुनर्निर्माण का केंद्र बनाने में गलत ही क्या है?

मौजूदा बहस और पीडीएनए रिपोर्ट शहरी शासन पर चुप है। केरल में कई समस्याएं बढ़ती शहरी आबादी के मुद्दे को हल करने में विफलता से उत्पन्न होती हैं। शहरी केरल में भारत में सबसे अधिक मासिक प्रति व्यक्ति खर्च है। नतीजतन, रिपोर्ट का अनुमान है कि केरल में दैनिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 10,044 टन है। यह कोलोसल डिजास्टर मलबे के अलावा है, जिसे साफ किया जाना अभी बाकी है। पुनर्निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में अतीत की ग्रामसभा भावना को पुनर्जीवित करना मुश्किल नहीं है। केरल नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा-55 में मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद् के गठन का प्रावधान है, जिसमें मंत्रिपरिषद् के सदस्य और पंचायतों और नगर पालिकाओं के नेताओं के सदस्य शामिल हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और

लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने इस संस्था को बर्बाद कर दिया है। राज्य विकास परिषद् को अम्ब्रेला संगठन (umbrella organisation) बनाया जा सकता है, जो पुनर्निर्माण परियोजना के केंद्र बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए नवा केरल मिशन और स्थानीय सरकार को एकीकृत करेगा।

बहुत से लोग केरल को हरा-भरा राज्य बनाने की बात करते हैं। एक हरे रंग की अर्थव्यवस्था कहर की समझ के बिना संभव नहीं है। भूमि उपयोग के पैटर्न और जल प्रबंधन में बदलाव से धान के क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है। 1960 के दशक में फसल क्षेत्र का 35% आज 7% हो गया है। चावल की खेती वाटरशेड के आधार पर की जाती है। आज जिस पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वह काफी हद तक धान की कटाई से जुड़ा है। चूंकि केरल संरक्षण धान भूमि और वेटलैंड अधिनियम को 2008 में पारित किया गया था, इसलिए सभी अवैध अपराधों के अनुसमर्थन के अलावा और कुछ नहीं हुआ।

जब तक हमें एहसास नहीं होता कि उत्खनन, धातु पेराई और रेत खनन माफिया केरल के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, कोई भी सार्थक भूमि उपयोग और खनन नीति लागू नहीं की जा सकती है। एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के लिए पीडीएनए सिफारिशों को कभी भी उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

सामाजिक बहिष्कार का अंत

एक सवाल यह भी है कि क्यों आदिवासियों और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे लोगों की अभी तक उपेक्षा कि जा रही है? अब समय आ गया है कि पुनर्निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में इस मुद्दे को भी उठाया जाये। वास्तव में, आपदाओं ने एक बार फिर से गरीबों की कमजोरियों के साथ-साथ बुजुर्गों, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। क्या केरल संरचनात्मक सुधारों और कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण करेगा?

एक सड़क नीति, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना है, पुनर्निर्माण परियोजना की एक और प्राथमिकता होनी चाहिए। 2018 में, लगभग 4,800 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। राज्य को एक सड़क पुनर्निर्माण नीति की आवश्यकता है, जो इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करेगी।

GS World टीम...

नवा केरल मिशन

परिचय

- इस मिशन का शुभारंभ 10 नवंबर, 2016 को केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में व्यापक विकास करना है।
- इस मिशन के तहत चार परियोजनाएँ शामिल हैं।
- इस मिशन की मुख्य पहल राज्य के विकास और मानचित्र पर केरल की स्थिति को तीव्र करना है।

उद्देश्य

- केरल सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों को विकसित करने की कोशिश कर रही है और भारत के नक्शे पर अपनी बेहतर स्थिति का निर्माण करना चाहती है।
- सरकार की योजना है कि परियोजनाओं को समयबद्ध आधार पर नागरिक निकायों के समर्थन से लागू किया जाए।
- ये योजनाएं स्थानीय सरकारों की मदद और भागीदारी के साथ जीवन के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आवास को संबोधित करेंगी।

शामिल चार परियोजनाएँ

हरिता केरल

- इसका मतलब है कि कृषि विकास के लिए जैविक खेती और जल स्रोतों को संरक्षित करना।
- इसमें विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
- यह उचित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परिणामस्वरूप, पर्यावरण समाज को स्वस्थ और कई बीमारियों से मुक्त रखेगा।

आर्द्रम (Ardram)

- इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार करना और उचित मूल्य पर उपचार को सक्षम बनाना है।
- यह राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक समुद्री बदलाव लाएगा।

शिक्षा व्यवस्था

- यह केरल की पब्लिक स्कूल प्रणाली को संरक्षित करने और मजबूत करने की एक योजना है, जिसमें नवीन शिक्षण विधियों को लाकर स्कूल प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा।
- यह योजना स्कूल प्रणाली के लिए है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण वितरित करना है। ताकि, हर छात्र को बुनियादी शिक्षा मिल सके।

जीवन योजना

- राज्य में बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, जो बेघर हैं। इसलिए सरकार बेघरों के लिए आवास उपलब्ध कराने और मिशन में जीवन की गुणवत्ता लाने का फैसला करेगी।
- योजना का लक्ष्य केरल में 4.32 लाख परिवारों के लिए घर बनाना है और इस योजना के लिए अनुमानित बजट 6000रु-6500 करोड़ रु है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'नवा केरल मिशन' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. इसका उद्देश्य आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में व्यापक विकास करना है।
   2. इस मिशन के तहत चार परियोजनाएँ शामिल हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements regarding the 'Nava Kerala Mission'-**

   1. It's objective is to bring about extensive development in the field of housing, health, education and agriculture.
   2. Under this mission four projects have been included.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: पिछले वर्ष केरल में आयी बाढ़ ने केरल के विकास में अनेक समस्याएं उत्पन्न कीं। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया नवा केरल मिशन इन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ तक प्रभावी होगा? इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए कौन-से उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए।

Q. The flood occured in Kerala last year created many hurdles in the development of Kerala. To what extent will the Nava Kerala Mission launched by the Kerala government be effective in addressing these hurdles? What measures are required to be adopted for its implementation? Discuss.

(250 Words)

नोट : 23 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World Committed To Excellence

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322